सूचित करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

वर्ष 2013 का दीवानी आवेदन संख्या (एस)1635

जगदीश प्रसाद सिंह **.....अपीलकर्ता**

बनाम

बिहार राज्य और अन्य **.....उत्तरदाता**

बिहार पेंशन नियम, 1950-- भुगतान निर्धारण-- पेंशन में कटौती-- ए. डी. एस. ओ. के पद से अपनी सेवानिवृत्ति के आठ साल से अधिक समय के बाद, अपीलार्थी को बिहार सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उसके वेतन निर्धारण में एक त्रुटि हुई थी और इसलिए, उससे रू० 63,765/- की राशि वसूल करनी थी क्योंकि उसका भुगतान उसकी पात्रता से अधिक किया गया था---- पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी के वेतन निर्धारण में संशोधन और परिणामी कमी 8 फरवरी, 1999 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार की गई थी, जिसके अनुसार, अपीलार्थी उच्च वेतनमान का हकदार नहीं था जो उसे गलत तरीके से दिया गया था, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दलीलों को खारिज कर दिया- इसलिए वर्तमान अपील।

आयोजित किया गया:अपीलार्थी को उसकी पात्रता के अनुसार पदोन्नत किया गया था और उसकी पदोन्नति में कोई अनियमितता नहीं थी-अपीलार्थी को संशोधित वेतनमान प्रदान करने में कोई अवैधता जो लागू नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की गई एक कार्रवाई थी-वेतनमान में कमी और अपीलार्थी से वसूली का निर्देश देने वाला आदेश स्पष्ट रूप से कोई कारणदर्शक नोटिस से पहले नहीं था और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया था-राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और वह भी लंबे समय के बाद। वेतनमान में कमी का कारण और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके कठोर असैनिक और साथ ही बुरे परिणाम हैं-विवादित कार्रवाई को दरकिनार कर दिया गया है-- अपील की अनुमति है। (पैरा 7,18-21)

(2009) 3 एससीसी 475, (2011) 7 एससीसी 493, (2015) 4 एससीसी 334,2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 ..... विश्वसनीय।

सूचित करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

वर्ष 2013 का दीवानी आवेदन संख्या (एस)। 1635

जगदीश प्रसाद सिंह .....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य और अन्य .....उत्तरदाता

निर्णय

मेहता, न्यायमूर्ति

1. सुना।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 27 अगस्त, 2012 को पटना में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 2011 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254 में पारित अंतिम फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया गया था और 23 फरवरी, 2010 का फैसला 2009 के दीवानी रिट अधिकारिता मामले (सी. डब्ल्यू. जे. सी.) संख्या 18542 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और इसी तरह 2010 की दीवानी समीक्षा संख्या 82 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 23 मार्च, 2011 के फैसले को भी बरकरार रखा गया।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि यहाँ अपीलार्थी को वर्ष 1966 में बिहार सरकार में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 15 साल तक सेवा करने के बाद, उन्हें पहली बार विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली और उन्हें 1 अप्रैल, 1981 से कनीय चयन संवर्ग में रखा गया। सेवा में 25 वर्ष पूरे करने पर, अपीलार्थी को वरिष्ठ चयन संवर्ग, विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी (संक्षेप में 'ए. डी. एस. ओ.') के पद पर 10 मार्च, 1991 को 2000-3800 रूपये के वेतनमान में पदोन्नत किया गया।

4. बिहार सरकार ने 8 फरवरी, 1999 को एक संकल्प जारी किया जिसमें विपणन अधिकारी के वेतनमान को 1640-2900 रूपये से 5500-9000 रूपये और विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकार के वेतनमान को 2000-3800 से 6500-10500 रूपये से संशोधित किया गया। चूंकि अपीलार्थी को 10 मार्च, 1991 से विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए उसके वेतनमान को 8 फरवरी, 1999 के संकल्प के अनुसार संशोधित कर 6500-10500 रूपये कर दिया गया था, जिसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया हैः-

> **"11. राज्य सरकार ने 18 दिसंबर, 1989 के एफ. डी. संकाय संख्या.6021 के कंडिका 10 और 12 में चर्चा की गई समयबद्ध पदोन्नति और चयन श्रेणी की मौजूदा सुविधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है और वे पहली जनवरी 1996 से समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद मौजूदा वेतनमानों में लागू होगा। *अगर ऐसा कोई है, हालांकि, पदोन्नति 1 जनवरी, 1996 से पहले नियमों के तहत देय है, यह दिया जाएगा और मौजूदा पैमाने में बकाया का भुगतान केवल 31 दिसंबर, 1995 तक किया जाएगा, जिसके बाद पदोन्नति को स्वचालित रूप से समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।*** जबकि संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करते समय, 31 दिसंबर, 1995 के बाद दी गई ऐसी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी पदोन्नति 31 दिसंबर, 1995 के बाद दी गई है, तो इस प्रक्रिया में प्राप्त इस तरह के अतिरिक्त परिलब्धियों के समायोजन का सवाल फिटमेंट समिति द्वारा पदोन्नति नीति पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद तय किया जाएगा। आवश्यकता आधारित पद के रूप में पहचाने गए पद की किसी भी रिक्ति पर पदोन्नति स्वीकार्य होगी। ऐसे आवश्यकता आधारित पदों की पहचान करने की प्रक्रिया पैराग्राफ 12 में निर्धारित की गई है।
>
> (जोर दिया गया)

5. अपीलार्थी 31 जनवरी, 2001 को विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के समय, अपीलार्थी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन स्वीकार्य परिलब्धियों के साथ 6500-10500 रूपये के वेतनमान में 10500 रूपये था। 1950 के बिहार पेंशन नियमों के अनुसार, उनकी पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत

पर की गई थी और प्रति माह 5247 रूपये पर निर्धारित की गई थी। तदनुसार, उपरोक्त पेंशन अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से वितरित की गई थी।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार राज्य के महालेखाकार ने 10 मार्च, 1991 को अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति के संबंध में 28 जनवरी, 2003 को एक और टिप्पणी के साथ आपत्ति जताई कि 8 फरवरी, 1999 का सरकारी संकल्प के मद्देनजर 10 मार्च, 1991 को अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति 1 जनवरी, 1996 के बाद अप्रभावी हो जाएगी और इस प्रकार, अपीलार्थी के वेतनमान को निचले पद यानी विपणन अधिकारी के वेतनमान से मेल खाने के लिए संशोधित और कम करना होगा।

7. अपनी सेवानिवृत्ति के आठ साल से अधिक समय के बाद, अपीलार्थी को बिहार सरकार से 15 अप्रैल, 2009 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उसके वेतन निर्धारण में एक त्रुटि हुई थी और इसलिए, उससे 63,765/- रूपये की राशि वसूल की जानी थी क्योंकि उसे उसकी पात्रता से अधिक भुगतान किया गया था। पत्र में अपीलार्थी को उपरोक्त राशि को एक बार या किश्तों में वापस करने का निर्देश दिया गया। उक्त पत्र की भाषा नीचे दी गई हैः-

> "उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि <u>आपके खिलाफ की गई विभागीय जांच के जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने</u> और विभाग के विश्लेषण के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि वेतन निर्धारित करने में गलती के कारण आपको 63,765/- रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जो आपसे वसूली योग्य है।
>
> कृपया यह स्पष्ट करें कि आप उक्त राशि का भुगतान एक बार में करेंगे या किश्तों में। कृपया आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों के भीतर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। "
>
> (जोर दिया गया)

8. वसूली सूचना और अपनी पेंशन में कमी से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अपनी पेंशन में कमी और प्रस्तावित वसूली के विरोध में बिहार सरकार को कई अभ्यावेदन दिए। तथापि, जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर नहीं दिया गया, अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष

2009 की रिट याचिका संख्या 6714 थी। उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2009 के आदेश के माध्यम से बिहार राज्य को अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, 4 सितंबर 2009 को, अपीलार्थी ने बिहार सरकार को एक और विस्तृत अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि 8 फरवरी, 1999 के सरकारी प्रस्ताव के अनुच्छेद 11 (*उपरोक्त*) की 15 अप्रैल, 2009 के पत्र में गलत व्याख्या की गई थी, ताकि अपीलार्थी को उसकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य वेतनमान के लाभ से वंचित किया जा सके, जिसके कारण उसके पेंशन लाभों में अन्यायपूर्ण कमी आई। अभ्यावेदन में एक प्रासंगिक याचिका ली गई थी कि अनुच्छेद 11 (*उपर्युक्त*) की व्याख्या अपीलार्थी के पूर्वाग्रह के लिए नहीं की जा सकती क्योंकि उसे 31 दिसंबर, 1995 से बहुत पहले समयबद्ध पदोन्नति दी गई थी और उक्त संकल्प विशेष रूप से उक्त तिथि से पहले की गई पदोन्नति की रक्षा करता है। इसलिए, अपीलार्थी ए. डी. एस. ओ. के प्रचार पद पर 6500-10500 रूपये के कोष्ठक में निर्धारित अपने वेतनमान की सुरक्षा प्राप्त करने का हकदार था।

9. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार ने 8 अक्टूबर, 2009 को एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए कहा गया कि अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति स्वचालित रूप से 31 दिसंबर, 1995 के बाद 8 फरवरी, 1999 के सरकारी संकल्प के आधार पर समाप्त हो जाएगी और इसलिए, उसके वेतनमान को संशोधित करना होगा और सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी को ए. डी. एस. ओ. के बजाय विपणन अधिकारी के पद पर मानते हुए इसे घटाकर 5500-9000 रूपये करना होगा।

10. अपीलार्थी ने उक्त आदेश को अस्वीकार करते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 18542 को प्राथमिकता दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23 फरवरी, 2010 के आदेश के *माध्यम* से उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

11. यह कहते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनकी शिकायतों का ठीक से समाधान नहीं किया गया था, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की समीक्षा याचिका संख्या 82 दायर की जिसे 23 मार्च, 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

12. उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 23 फरवरी, 2010 के आदेश और 23 मार्च, 2011 के आदेश को चुनौती देने वाली 2011 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 815 को चुनौती देते हुए 2011 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254 के रूप में दो लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। विद्वान खंड पीठ ने 24 अगस्त, 2012 के आदेश *द्वारा* 2011 के एल. पी. ए. सं. 815 को बनाए रखने योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि 2011 के एल. पी. ए. सं. 1254 को दिनांक 27 अगस्त 2012 के आदेश *द्वारा* खारिज कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी के वेतन निर्धारण में संशोधन और परिणामी कमी 8 फरवरी, 1999 के सरकारी प्रस्ताव के पैराग्राफ 11 (*उपरोक्त*) के अनुसार की गई थी, जिसके अनुसार अपीलार्थी उस उच्च वेतनमान का हकदार नहीं था जो उसे गलत तरीके से दिया गया था। उक्त आदेश इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा लागू किया जाता है।

<u>अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः-</u>

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित आदेश कानून की नजर में *प्रत्यक्ष रूप से* खराब हैं क्योंकि 8 फरवरी 1999 के सरकारी प्रस्ताव की अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी गलत व्याख्या की गई थी। उन्होंने आग्रह किया कि 8 फरवरी 1999 के सरकारी संकल्प के पैराग्राफ 11 (*उपरोक्त*) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 31 दिसंबर 1995 से पहले समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए, अपीलार्थी को 10 मार्च, 1991 को वरिष्ठ चयन ग्रेड, विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी के रूप में समयबद्ध पदोन्नति दी गई थी, जो उक्त सरकारी संकल्प, यानी 31 दिसंबर, 1995 के तहत निर्धारित कट ऑफ तिथि से बहुत पहले थी और इस प्रकार, उसे संशोधित वेतनमान का लाभ 6500-10500 रूपये पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदान किया गया था। 8 फरवरी, 1999 के सरकारी संकल्प में स्पष्ट रूप से 31 दिसंबर, 1995 के रूप में कट-ऑफ तिथि का संकेत दिया गया था, अपीलार्थी को इसके प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षित किया जाएगा और वह अपनी पदोन्नति और वेतनमान की रक्षा करने का हकदार था। इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी के वेतनमान में कमी और उसकी सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद वसूली करने का निर्देश, वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना, अन्यथा अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और इस प्रकार, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 8 फरवरी, 1999 के सरकारी संकल्प की व्याख्या करते समय स्पष्ट रूप से गलती की क्योंकि इसका अनुच्छेद 11 (ऊपर *दिया* गया) 10 मार्च, 1991 को अपीलार्थी को दी गई समयबद्ध पदोन्नति की रक्षा करता है और इसी तरह 5 वें वेतन आयोग के तहत उक्त पद पर लागू संशोधित वेतनमान की भी रक्षा करता है।

15. इन आधारों पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने न्यायालय से आक्षेपित आदेशों और प्रस्तावित अपीलार्थी से वसूली आग्रह किया और इसी तरह उसके भविष्य के पेंशन लाभों में परिणामी कमी को रद्द करने का आग्रह किया।

<u>उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुतियाँः-</u>

16. *इसके विपरीत,* बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का जोरदार और उत्साहपूर्वक विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि 8 फरवरी, 1999 के सरकारी प्रस्ताव को बिहार राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू किया गया था। अपीलार्थी को आक्षेपित कार्रवाई के लिए अलग नहीं किया गया है और इस प्रकार, अपीलार्थी के साथ किसी भी तरह के भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। महालेखाकार के कार्यालय ने अपीलार्थी को संशोधित वेतनमान देने में स्पष्ट त्रुटि/अनियमितता देखी थी और इस प्रकार, 15 अप्रैल, 2009 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को गलत वेतनमान दिए जाने के कारण प्राप्त अतिरिक्त राशि को वापस करने की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 8 फरवरी, 1999 के सरकारी संकल्प की सही व्याख्या की और अपीलार्थी को राहत देने से इनकार करने वाले तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया और इस प्रकार, अपीलार्थी इस न्यायालय से भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत इस अपील में अनुग्रह की मांग करने का हकदार नहीं है। उन्होंने अपील को खारिज करने का आग्रह किया।

चर्चा और निष्कर्षः-

17. हमने बार में अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

18. शुरुआत में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थी को 10 मार्च 1991 को उसकी पात्रता के अनुसार कनिष्ठ चयन श्रेणी में विपणन अधिकारी के पद से वरिष्ठ चयन श्रेणी, विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी (ए. डी. एस. ओ.) के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दिए जाने के बारे में कोई विवाद नहीं है। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि उक्त पदोन्नति किसी अनियमितता से ग्रस्त थी या नियमों और विनियमों के खिलाफ दी गई थी। 19 जनवरी, 1991 को अनुलग्नक पी-1 के रूप में अभिलेख में रखा गया प्रस्ताव इंगित करता है कि निचले वरिष्ठ ग्रेड (विपणन अधिकारी) के पद से अगला प्रचार चैनल उच्च वरिष्ठ ग्रेड (उच्च विपणन अधिकारी) के पद पर था। इससे पहले निम्न उच्च संवर्ग (मार्केटिंग ऑफिसर) के पद के लिए वेतनमान 1800-3330 रूपये तय किया गया था, जबकि पदोन्नति पद यानी उच्च वरीय संवर्ग (विपणन अधिकारी) के लिए लागू वेतनमान 2000-3000 रूपये किया गया था। अपीलार्थी को 10 मार्च, 1991 से विधिवत उच्च वरिष्ठ श्रेणी (उच्च विपणन अधिकारी) के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसे पदोन्नति पद का वेतनमान दिया गया था। 5 वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, बिहार सरकार ने 8 फरवरी, 1999 को एक प्रस्ताव जारी किया, जिसके तहत उच्च वरिष्ठ ग्रेड (उच्च विपणन अधिकारी) के पद पर लागू वेतनमान को 2000-3800 रूपये से 6500-10500 रूपये में संशोधित किया गया था। उक्त सरकारी प्रस्ताव का अनुच्छेद 11 (ऊपर दिया गया) विशेष रूप से 31 दिसंबर, 1995 से पहले कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति की रक्षा करता है। केवल वे कर्मचारी जिन्हें कट ऑफ तिथि, यानी 31 दिसंबर, 1995 तक पदोन्नत नहीं किया गया था, उन्हें एक काल्पनिक पदोन्नति और वेतनमान में परिणामी वृद्धि मिलेगी जो 31 दिसंबर, 1995 से समाप्त हो जाएगी। जाहिरा तौर पर इस प्रकार, अपीलार्थी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था और उक्त प्रस्ताव के आधार पर उसके वेतनमान को संभावित रूप से कम नहीं किया जा सकता था। भले ही अनुच्छेद 11 (उपर्युक्त) अस्तित्व में न हो, अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद भी सजा नहीं

दी जा सकती थी क्योंकि अपीलार्थी को संशोधित वेतनमान प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं थी, जो लागू नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई थी।

19. 15 अप्रैल, 2009 का आदेश, जिसके तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया गया था कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण अधिक भुगतान की गई 63,765/- रूपये की राशि की वसूली करने का निर्णय लिया गया था, यह भी इंगित करता है कि अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी, जिसके कारण आक्षेपित कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में किए जा रहे एक प्रासंगिक प्रश्न पर, विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थी के खिलाफ ऐसी कोई विभागीय जांच कभी नहीं की गई थी।

20. उपरोक्त निष्कर्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हमारा विचार है कि राज्य द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति के आठ साल बाद कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के बाद नियोक्ता कर्मचारी संबंध समाप्त हो गए थे। वेतनमान में कमी और अपीलार्थी से वसूली का निर्देश देने वाला आदेश स्पष्ट रूप से किसी कारण दर्शाओ नोटिस से पहले नहीं था और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका संख्या 6714 में पारित 20 जुलाई, 2009 के आदेश के अनुसार, उन्होंने सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 8 अक्टूबर, 2009 के आदेश के माध्यम से एक व्यक्तिगत सुनवाई से पहले खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि सचिव का विचार था कि सरकारी संकल्प के पैराग्राफ 11 (उपरोक्त) के अनुसार, अपीलार्थी की पहली/दूसरी बार की जाने वाली पदोन्नति 1 जनवरी, 1996 को स्वचालित रूप से समाप्त हो गई थी और इस प्रकार, अपीलार्थी को विपणन अधिकारी के पद पर फिर से नामित करने की आवश्यकता थी और वह फिटमेंट समिति द्वारा अनुशंसित 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतन का हकदार होगा। इस प्रकार, इस आदेश में भी, अपीलार्थी को 10 मार्च, 1991 को ए. डी. एस. ओ. के पद पर दी गई पदोन्नति पर कोई संदेह नहीं है।

21. हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं

किया जा सकता है और वह भी एक लम्बे अंतराल के बाद। ***सैयद अब्दुल कादिर और अन्य में बनाम बिहार राज्य और अन्य*** [1] के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कम समय के भीतर अतिरिक्त अनधिकृत भुगतान का पता चलता है, तो नियोक्ता के लिए उसी की वसूली करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत, यदि भुगतान लंबे समय के लिए किया गया था, तो कोई भी वसूली करना अनुचित होगा। ***सैयद अब्दुल कादिर*** (उपरोक्त) के प्रासंगिक कंडिका नीचे निकाले गए हैंः-

> **"57.** इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में, परिलब्धियों/भत्तों के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के खिलाफ राहत दी है यदि (ए) कर्मचारी की ओर से किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, और (बी) यदि ऐसा अतिरिक्त भुगतान नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है।
>
> **58.** वसूली के खिलाफ राहत अदालतों द्वारा कर्मचारियों में किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी जाती है, बल्कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत देने के लिए दी जाती है जो वसूली का आदेश दिए जाने पर होंगी। लेकिन, यदि किसी मामले में, यह साबित हो जाता है कि कर्मचारी को जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या ऐसे मामलों में जहां त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर सुधार किया गया है, मामला न्यायिक विवेक के दायरे में है, तो अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश दे सकती हैं।
>
> **59.** निस्संदेह, अपीलार्थी शिक्षकों को जो अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, वह उनकी ओर से किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं था और अपीलार्थी को यह भी जानकारी नहीं थी कि उन्हें जो राशि दी जा रही थी, वह उनके अधिकार से अधिक थी। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि वित्त विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि यह उनकी ओर से एक वास्तविक गलती थी। अतिरिक्त भुगतान उस नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था जो उन पर लागू था, जिसके लिए अपीलार्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि, पूरा भ्रम बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और लापरवाही के कारण था। अपीलार्थी शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

अधिकांश लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इसके कगार पर हैं। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपीलार्थी शिक्षकों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी शिक्षकों को अधिक भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। **"**

(जोर दिया गया)

22. इसी तरह, ***आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** [2] मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"108. हम सेवा न्यायशास्त्र से एक उदाहरण दे सकते हैं, जहां किसी कर्मचारी को कुछ समान परिस्थितियों में राहत देने के लिए समानता के सिद्धांत का अक्सर उपयोग किया जाता है। जहां किसी कर्मचारी को देय वेतन या अन्य परिलब्धियों का नियोक्ता द्वारा निर्धारण और भुगतान किया जाता है, और बाद में नियोक्ता (आमतौर पर ऑडिट सत्यापन पर) पाता है कि नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा लागू नियमों की गलत समझ के कारण, अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, अदालतों ने पिछले अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के संबंध में सीमित राहत देने की आवश्यकता को मान्यता दी है, ताकि निर्दोष कर्मचारियों की कठिनाई को कम किया जा सके, जिन्हें इस तरह की गलत व्याख्या से लाभ हुआ। **"**

(जोर दिया गया)

23. ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेद धोबी) और अन्य*** [3] के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः इसके अंतर्गतः-

"18. उन सभी कठिनाइयों की स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करती हैं, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, जो उनकी पात्रता से अधिक है। चाहे जो भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगीः

(I) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली के आदेश से।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किया गया है, और उसी के अनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे किसी निम्न पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आवश्यक किया गया हो।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी। **"** (जोर दिया गया)

24. हाल ही में, यह न्यायालय ***थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य*** [4]मामले में इस न्यायालय ने कहा कि राज्य 10 साल की देरी के बाद पूर्व कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकता है।

25. 8 फरवरी, 1999 के सरकारी संकल्प में विशेष रूप से कहा गया है कि यह उन कर्मचारियों की स्थिति और वेतन की रक्षा करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 1995 से पहले अपनी समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त की थी। परिणामस्वरूप, संबंधित सचिव ने अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या की और अपीलार्थी के नुकसान के लिए उक्त संकल्प को गलत तरीके से लागू किया।

26. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ भी इसी त्रुटि में पड़ गई है। इसके अलावा, हमारा मानना है कि वेतनमान में कमी और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर दीवानी और साथ ही बुरे परिणाम भी होते हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से, क्योंकि वह उन्हें 10 मार्च, 1991 को इस पद पर लागू होने वाले 6500-10500 रूपये के वेतनमान के साथ ए. डी. एस. ओ. के रूप में पदोन्नत किया गया था और आठ साल पहले 15 अप्रैल, 2009 को वसूली सूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त भी हो गए थे। वेतनमान में कमी और अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देने वाली आक्षेपित कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना और अवैध है और

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के दोष से भी ग्रस्त है और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

27. राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर, 2009 को पारित आदेश में अपीलार्थी के वेतनमान को 1 जनवरी, 1996 से घटाकर 6500-10500 रूपये से 5500-9000 रूपये करने का निर्देश दिया गया और उससे अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देना सरासर अवैध और मनमाना है और इसे रद्द है और दरकिनार कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 27 अगस्त, 2012 का आक्षेपित आदेश जांच के दायरे में नहीं आता है और इसे निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए, अपीलार्थी को **Rs**.6500-10500 के वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलती रहेगी।

28. यदि आक्षेपित आदेशों के कारण पेंशन और परिणामी वसूली में कोई कमी की गई थी, तो अपीलार्थी लागू ब्याज के साथ उसकी बहाली/प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

29. इन शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

.....न्यायमूर्ति

(संदीप मेहता)

.....न्यायमूर्ति

(आर.महादेवन)

नई दिल्ली;

08 अगस्त, 2024

[1] (2009) 3 एससीसी 475

[2] (2011) 7 एससीसी 493

[3] (2015) 4 एससीसी 334

[4] 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।